



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208]
No. 208]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 1998/भाद्र 25, 1920
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 1998/BHADRA 25, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या-41 (आर ई-98)/1997—2002

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1998

फा. सं. पी आर यू/ए एस/97-98/स्पेशल पैकेज.—सांविधिक आदेश संख्या-283(स) दिनांक 31-3-97 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड-2 में यथाअधिसूचित अनुसार निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 4.11 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण-98) 1997—2002 में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. पैराग्राफ 7.4 (ड.) के बाद निम्नलिखित को पैराग्राफ 7.4 (घ) के रूप में जोड़ा जाएगा :
“इलैक्ट्रानिक उत्पादों के निर्यातकों को परिशिष्ट-53 में उल्लिखित अनुसार इलैक्ट्रानिक्स उत्पादों के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम का लाभ उठाने का विकल्प उपलब्ध होगा।”
2. इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक को परिशिष्ट-53 के रूप में रखा जाएगा।
इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक,
विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

परिशिष्ट-53

इलैक्ट्रानिक्स उत्पादों के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम

1. पात्रता :

केन्द्रीय उत्पन्न शुल्क प्राधिकारियों और इलैक्ट्रानिक और सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद् के पास पंजीकृत विनिर्माता निर्यातक, जिन्होंने विगत

तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यात/घरेलू उत्पादन किया हो, इस स्कीम के अन्तर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे।

2. हकदारी :

पात्र निर्यातक, विगत तीन वर्षों में किए औसत पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 150% तक, उत्पादन कार्यक्रम आधार पर अग्रिम लाइसेंस हेतु हकदार होंगे। नए निर्यातक, बिना किसी निर्यात निष्पादन के, विगत तीन वर्षों में औसत घरेलू उत्पादन के 50% तक अथवा 50 लाख रुपये तक, जो कोई अधिक हो, के अग्रिम लाइसेंस के भी हकदार होंगे। निर्यातक के आवेदन करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी पूरे किए गए निर्यातों की सीमा तक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत और लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं।

3. स्कीम :

- (क) पात्र निर्यातक स्कीम के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेंस मंजूर करने हेतु आवेदन कर सकता है।
- (ख) ऐसे लाइसेंस सकारात्मक मूल्य संवर्धन के साथ जारी किए जाएंगे।
- (ग) स्कीम के अन्तर्गत आयात से पूर्व निर्यात करना होगा और ऐसे लाइसेंस वास्तविक प्रयोक्ता गैर-हस्तान्तरणीय शर्त के साथ जारी किए जाएंगे।
- (घ) आयातित सामग्री/निवेशों की घरेलू बिक्री की अनुमति नहीं होगी, अपशिष्ट हेतु विनिर्दिष्ट सीमाओं तक स्कैप की बिक्री इसका अपवाद होगी।
- (ड.) अग्रिम लाइसेंस, आवेदक द्वारा निविष्टियों और इसकी मात्रा के विवरण के संबंध में घोषणा करने पर क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। निविष्टियों की तकनीकी विशिष्टि को लाइसेंसों में निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा। तथापि, आयातक आगम पत्र और डी ई ई सी (आयात) में सीमा

शुल्क प्राधिकारी को वस्तुओं की निकासी के समय तकनीकी विशिष्टि के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

- (च) लाइसेंसधारक सामग्री का आयात या निजी बांडेड गोदाम से वस्तुओं को प्राप्त करने से पूर्व सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास आवश्यक बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।
- (छ) लाइसेंस धारक डी ई ई सी (आयात) में ब्यौरे दर्ज करेगा और आयातित वस्तुओं के प्रमाणीकरण के लिए इन ब्यौरों को सीमा-शुल्क प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (ज) इलैक्ट्रानिक्स विभाग का नामजद अधिकारी निर्यात-उत्पाद में निविष्टियों की प्रासंगिकता/उपयोगिता और अपेक्षित मात्रा की जांच करेगा। इलैक्ट्रानिक्स विभाग का नामजद अधिकारी निर्यातित उत्पाद में निविष्टियों की वास्तविक उपयोगिता और निर्यात उत्पादों के संबंध में अपशिष्ट की जांच भी करेगा, आयातित निविष्टियों की उपयोगिता का निर्धारण पहले से मौजूद ऐसे मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा और जहां कहीं ऐसे मानदंड मौजूद नहीं हैं, इनका निर्धारण इलैक्ट्रानिक्स विभाग के नामजद अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- (झ) इलैक्ट्रानिक्स विभाग के नामजद अधिकारी का प्रमाण-पत्र डी ई ई सी पुस्तक में प्रविष्टि करने के लिए सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जायेगा और इसके पश्चात् विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने और सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करने के लिए उक्त प्रमाण-पत्र को स्वीकार किया जायेगा।
- (ञ) निर्यातक निर्धारित प्रपत्र में छमाही आधार पर इलैक्ट्रानिक्स विभाग के नामजद अधिकारी को किये गये आयात और निर्यात के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।
- (ट) निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 5.15 के अधीन निजी बांडेड गोदाम से निविष्टियों को प्राप्त करने की सुविधा भी लागू होगी।

3. निर्यात दायित्व की अवधि समाप्त होने के पश्चात् इस्तेमाल न की गयी छूट प्राप्त सामग्री पर 24% वार्षिक ब्याज सहित सीमा-शुल्क का भुगतान करना होगा और ऐसे अतिरिक्त आयात के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 5 गुना के बराबर विशेष आयात लाइसेंस को वापस करना होगा यदि आयातित निविष्टियों आयात की निषेधात्मक सूची में आती हैं।

4. नीति और प्रक्रिया के अध्याय 7 में दी गयी शुल्क मुक्त योजनाओं के अन्य प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस स्कीम के तहत निर्धारित सीमा तक लागू होंगे।

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 41 (RE-98)/1997—2002

New Delhi, the 16th September, 1998

F. No. PRU/AS/97-98/Special Package.—In exercise of powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997—2002, as notified in the

Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S. O. No. 283(E) dated 31-3-97, the Director General of Foreign Trade hereby makes following amendment in the Handbook of Procedures (Vol. I) (RE-98), 1997—2002 :—

1. The following shall be added as paragraph 7.4 (f) after paragraph 7.4(e) :

“The eligible exporters of Electronic products shall have the option to avail the Special Advance Licensing Scheme for export of electronics products as given in Appendix 53.”

2. The Annexure to this Public Notice shall be numbered as Appendix 53.

This issues in public interest.

N. L. LAKHANPAL, Dir. Gen. of Foreign Trade
and Ex-Officio Addl. Secy.

Appendix 53

Special Advance Licensing Scheme for Export of Electronics Products

1. Eligibility :

The manufacturer exporters registered with the Central Excise Authorities and Electronic and Software Export Promotion Council having export performance/domestic production in proceeding three licensing year will be eligible to apply under this scheme.

2. Entitlement :

The eligible exporter shall be entitled for Advance licence on production programme basis upto 150% of the average FOB value in the proceeding three years. The new exporter, without having any export performance, would also be entitled to the Advance licence upto 50% of the average domestic production in the proceeding three years or upto Rs. 50 lakhs whichever is higher. The licensing authorities may grant, an application of the exporter, further licences under production programme to the extent exports have been completed.

3. Scheme :

- (a) An eligible exporter may apply for the grant of Advance licence under the scheme.
- (b) Such licenses shall be issued with positive value addition.
- (c) The imports under the scheme shall precede exports and such licenses shall be issued with Actual User non transferable condition.
- (d) Domestic sale of Import material/inputs shall not be allowed except of scrap upto the specified limits fixed for wastage.
- (e) The Advance licence will be issued by the regional licensing authorities on the declaration of the

applicant regarding the description of inputs as well as its quantity. The technical specification of the inputs shall not be specified in the licenses. However, the details of the technical specification would be furnished by the importer to the Customs in the Bill of Entry and DEEC (Imports) at the time of clearance of the goods.

- (f) The licence holder shall execute necessary BG/LUT with the Customs before importing the material or procuring from Private Bonded Warehouse.
- (g) The licence holder shall enter the details in the DEEC (Imports) and present the same to the Customs for certification of the goods imported.
- (h) The Designated officer of the Deptt. of Electronics will verify the relevance/usability of the inputs in the export product as well as the quantity required. The designated officer of the Deptt. of Electronics shall also verify the actual utilisation of the inputs in the product exported as well as the wastage in respect of export products covered under standard Input Output Norms, the utilisation of inputs imported would be determined in accordance with such pre existing Standard Input Output Norms and where such norms do not exist, as per the deter-

mination of the designated officer of the Deptt. of Electronics.

- (i) The Certification by the designated officer of the Deptt. of Electronics shall be accepted by Customs for logging of DEEC books and thereafter by DGFT for issuance of No Objection Certificate for discharge of BG/LUT by Customs authority.
- (j) The exporter shall furnish the details of imports and exports made to the designated officer of the Deptt. of Electronics on 6 monthly basis in the prescribed form.
- (k) The facility of sourcing inputs from Private Bonded Warehouse under paragraph 5.15 of Exim Policy will also be applicable.

3. The exempt material which remain unutilised after the expiry of export obligation period, shall be liable for payment of Customs duty together with 24% interest per annum and surrender of SIL equivalent to 5 times the CIF value of such excess imports, if the imported inputs is under the negative list of imports.

4. The other provisions of the duty exemption schemes given in Chapter 7 of Policy and Procedure shall mutatis-mutandis apply to the extent that they are not inconsistent with this scheme.

